RE. SYNOPSIS OF PROCEEDINGS OF THE RAJYA SABUA

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): Sir, before you go to the Calling Attention, I have got a serious submission to make which affects all the Members of this House and the Secretariat of the Rajya Sabha. If you please see the Synopsis of Monday, the 28th July, 1980, you will find that the speeches which have been made by both the Opposition and the ruling party have been so well edited that it gives a very misleading impression. I say 'well edited" because all the Members who took part in the debate praised Mr. Satyajit Ray, including Mr. Sathe the Minister of Information and Broadcasting. Please listen to me. This is not an innocent thing. This is the result of some clever editing. All references in praise of Mr. Satyajit Ray have been omitted and blacked out; only references to Mr. Satyajit Ray where aspersions were made on him have been summarised in the Synopsis. All the references by me and other Members have all been omitted and blacked out; only those portions where Mr. Satyajit Ray has been ridiculed, attacked and criticised have been given. It is not so innocent. It is not fair. It gives a misleading impression about an outstanding director of the country. This has been done deliberately. Are the Synopsis edited by some censor sitting in some room? Mr. Satyajit Ray has been vilified in the Synopsis. All praises have been totally eliminated.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Generally, I do not speak on this. Sir, I would request you to look into this, because...

MR. CHAIRMAN; If only you give ma a chance to say this. I will personally look into it and compare the summary and the proceedings. If there is anything, I will issue a supplementary bulletin. You don't have to rub the thing so much. There is a very good English proverb—I do not know whether I am wise or not—"a word to the wise".

Now we shall take up the Calling Attention Motion.

Mr. Pandey:.... Just a minute, we are changing horses just now.

[The Vice-Chairman (Shri R. R. Morarka) in the Chair].

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

N\ a-implementation of the decision taken by Government after nationalisation of Coal Mines, for converting the Gorakhpur Central Labour Department into a Central Employment Exchange

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Uttar Pradesh): I call the attention of the Minister of Labour to the non-implementation of the decision taken by Government after nationalisation of coal mines, for converting the Gorakhpur Central Labour Department into a Central Employment Exchange which is causing hardship to lakhs of labourers from the eastern part of U.P., and the steps taken by Government in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Central Labour Depot in Gorakhpur was established in the year 1942, primarily to meet the growing demand for labour for the active forward areas of Assam in connection with the building of roads. Later, it continued to meet the demand for

labour to build aerodromes and railway projects. Sc cnetime in the middle o'f 1943, a baieh of workers was sent as an exper mental measure to work in the Sinj ireni Collieries. In course Of time a iumber of collieries in Bengal, Bihar and Andhra Pradesh, where ther. was shortage of local labour, began to rely on workers from Gorak lpur. At the instance of the the n Government of India, various mi ie owners joined to form the Coalfiel Is Recruiting Organisation in 1946. The Organisation entered into an agreement with the Gorakhpur Labour Depot to recruit labour. Workei 3 went out for periods of 11 months of employment and returned on r jplacement by other workers.

With the natio lalisation of coal mines, this systen of contract labour was progressively replaced by recruitment Of workers en regular and long term employment

As the scope foi employment in the coal mines declined it was decided early in 1976 to :onvert the Labour Depot into a C< ntral Employment Exchange to prov de employment opportunities to un killed workers of the area to work i *1* various public and private sector an 1 public sector establishments. H iwever, with the States actively encouraging employment through th'ir own exchanges, the demand on tike Central Employment Exchange has been declining. Many of the facilr ies built in Gorakhpur for the assembly of workers, their medical examination and the maintenance of t eir accounts are being used less a d less. A team of two senior officers have been deputed to Gorakhpur to explore what alternative use can bmade of the land, the buildings an i other facilities which are now id *2.*

771 RS—6.

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : उप-सभाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अर्ज.बो गरीब हालत है। गोरखपुर में 1942 में जब कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था वहाँ पर चूंकि जमीन पर मजदूरों का भार बहुत है और खेती कम है इसलिए आप जानते होंगे कि सारी दुनिया के देशों में खास तौर से अफरीका, मलेशिया, सिंगापुर में और दूसरे प्रदेशों में हमारे गोरखपुर के और इस्टर्न पार्ट आफ उत्तर प्रदेश के लाखों-लाख मजदूर आ कर के रोजी कमाते थे और जो कुछ पाते थे उससे अपने बाल, बच्चों का पोषण करते थे। श्रीमन्, आप जानते हैं कि कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ना लेकिन पेट की मजबूरी के कारण वे काम पर निकल जाते हैं और कहीं जा कर के रोजी की तलाश करते हैं। ऐसे समय में 1942 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में गोरखपुर में लेबर डिपार्टमेंट का सर्जन किया गया जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर से हमारे वे लोग जिनको कोई काम नहीं है, जो खेती के बोझ से अलग हैं वे जा कर के काम पा सकें और उन्होंने श्रीमन्, बड़ा यूजफुल काम किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल माइन ओनर्स ने गवर्नमेंट के पास अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद उन्होंने कहा कि गोरखपुर और पुर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों की बहुत जरूरत है और इसलिए हम चाहते हैं कि वे मजदूर हमारे कोल माइन्स में काम करें। वे मजदूर जिन्होंने हजारों गज जमीन के नीचे कोयले की खदान अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए की, श्रीमन्, उन्होंने अपने श्रम की बदौलत एक बड़ा स्थान प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने उनका एक्सप्लायटेशन करना शुरु किया। जब एक्सप्लायटेशन शुरु हुआ और कोल माइन ओनर्स ने उनके साथ गुलामों की तरह से बर्ताव करना शुरु किया। ऐसे समय में हमारे मंत्री जी ने जबकि कोल नेशनलाइ-जेशन 1972 में हुआ तो 1973 में सी० आर० ओ० की एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह तय

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

किया गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों का शोषण बन्द होना चाहिए जो कोयला खानों में काम करते हैं। उनमें रिफार्म लाने चाहिएं। पहली मीटिंग हुई। श्रीमन्, माननीय कल्याण राय जी हमारे राज्य सभा के मेम्बर हैं, माननीय नागेश्वर प्रसाद शाही जी मेम्बर हैं और मैं उस समय लोक सभा में था। मैंने तथा हमारे प्रदेश के सारे विधायकों और पार्लियामेंट के अधिकांश सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी को एक मेमोरेंडम दिया कि इस रिक्रूटिंग सेंटर को, इंडियन कोल माइनर्स, हमारी जो श्रम की पूंजी है, जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, इसको बन्द किया जाए। उनको खुद गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के जरिये अपने प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में भर्ती करे और जहां भी जरूरत हो उनका इनरोलमेंट करके उनको भेजा जाए। श्रीमन् यह पद्धति गवर्नमेंट ने लागू की, कमेटी बनी और सी आर ओ को एबालिश किया। उस एबालीशन के बाद यह सोचा गया कि आखिर कौन सा काम इनको दिया जाये। श्रीमन् उस समय यह एक सुझाव आया कि एक सेंट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बनाया जाये जिसमें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लाखों लाख मजदूर रोजी की तलाश में कहीं जाते हैं, इनको मजदूरी मिल सके और उनको आज अच्छी तरह से सुख सुविधा से रखा जा सके। श्रीमन्, सन् 62 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ और गवर्नमेंट आफ इंडिया को जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने को बार्डर रोड कन्सट्रेक्शन के लिए पेश किया। बहुत से हमारे प्रदेशों और दूसरे प्रदेशों में जो पब्लिक सेक्टर में काम हुए, चाहे बिजली के कारखाने लगाने के काम हुए, चाहे नहरें बनाने के काम हुएं, उनमें उनको भर्ती किया गया।

श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि जो वे कोल माइनर्स थे उनको तो एबालिश किया गया परन्तु आज सेन्ट्रल लेबर एक्सचेंज की स्थिति क्या हो गयी है। इसकी स्थिति हो गयी है कि गवर्नमेंट ने स्वयं एक नोटीफिकेशन जारी किया था। उस नोटीफिकेशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह 27 मार्च, 1976 का नोटीफिकेशन है और इसको एकाउटेंट जनरल के पास भेजा गया कि इसके लिए, जो सेंट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बनाया जायगा, कौन-कौन से लोग रहेंगे, कौन-कौन से आफीशियल रहेंगे, कितना स्टाफ रहेगा। 27 मार्च, 1976 को गवर्नमेंट ने नोटीफिकेशन के द्वारा यह कहा कि यह जो सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की स्कीम है इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि स्टाफ को सेंक्शन कर दिया क्लास थ्री, क्लास टू और क्लास वन के स्टाफ को सेंक्शन किया। लेकिन श्रीमन्, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हुई और जनता गवर्नमेंट आयी तब उन्होंने इस नोटीफिकेशन को अमेंड किया तथा उसके बाद नोटीफिकेशन के जरिये स्टाफ का करटेलमेंट शुरू किया। स्थिति यह हो गयी, श्रीमन्, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो डिप्टी डाइरेक्टर लेबर वहां पर पोस्टेड थे--नवम्बर, 1979 में वह बिल्डिंग जो चार एकड़ में है और 11 एकड़ में बैरेक्स बने हुए थे बिछिया कैम्प के पास, करीब-करीब इतनी जमीन थी, जिसमें मजदूर जाते थे, भर्ती होते थे, रहते थे, उनका निवास स्थान था, उसने पूरी उस बिल्डिंग को जो सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग है, जब वे रिटायर होने लगे तो जनता गवर्नमेंट से छः महीने का रिटायरमेंट का एक्सटेंशन लिया और एक्सटेंशन लेने के बाद उस बिल्डिंग को अपने नाम अपने दस्तखत से, बिना किसी लॉ के, बिना किसी अथारिटी से एलाट करा लिया। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आप अगर डिप्टी चेयरमैन हों या किसी जगह के जिलाधीश हों या किसी पद पर हों तो आप उस बिल्डिंग को अपने नाम से, अपने पर्सनल नाम से एलाट करा लें।

दूसरे साहब श्री बी० पी० सिंह जो रेलवे के एकाउंटेंट अफसर थे जब वे उनके रिटायरमेंट के बाद आये तो उन्होंने कहा कि तुम भी इसी बिल्डिंग में आधी बिल्डिंग एलाट करा लो। उन्होंने भी आधी एलाट करा ली। अब वहां के कागजात का क्या हुआ, वहां के असेट्स का क्या हुआ, वहां की जो बैरेक्स बनी हुई थीं उनके स्टाफ का क्या हुआ? उनको उन बैरेक्स में भेज दिया गया जो कि मजदूरों के रिक्रूटमेंट के लिए रखी गयी थी। यह सिचुएशन है। जब मैं मेम्बर आफ पार्लियामेंट राज्य सभा हुआ तो मैंने गवर्नमेंट आफ इंडिया के लेबर डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री जी को फौरन खत लिखा और मैंने कहा कि यह स्टेट आफ अफेयर है। यह सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट स्कीम करीब-करीब प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंजूर की थी, कैबिनेट ने सैंक्शन किया था, प्रेजीडेंट ने नोटीफिकेशन किया था, यह नोटीफिकेशन है, ये सारे कागजात हैं परन्तु आपके जो डिप्टी डाइरेक्टर लेबर हैं वे रिटायरमेंट करने के बाद अपनी पोजीशन को मिस यूज कर इसे समाप्त करा रहे हैं। यह बहुत जांच पड़ताल तथा सूझबूझ के बाद स्कीम तैयार की गयी थी।

श्रीमन्, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। मैं भी भगवान का भक्त हूं, भगवान में मेरी बड़ी आस्था है। वे ओवरनाइट साईं बाबा के चेले बन गये। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर श्री बलवन्त सिंह जो आये थे, वे भी साईं बाबा के चेले बन गये। श्रीमन्, एक "साईं समिति" बन गयी और "साईं समिति" ने एप्लाई किया कि इस बिल्डिंग को हमें दे दिया जाये। अब श्रीमन्, समझें कि चालीस हजार मजदूर जहां आकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ये जो "साईं समिति" और भगवान के प्रियपात्र लोग हैं जिनको केवल भगवान दिखाई देता था, उन्होंने लाखों लाख इन्सानों का जिनको भगवान देखता है कि वे गरीबी से तड़प रहे हैं जो दुनिया में मजदूरी करने जा रहे हैं, जो सिंगापुर में चौकीदारी करते हैं, जो दूसरी जगहों पर काम करते हैं, इन लोगों ने जब बिल्डिंग को एलाट कराना चाहा तो मुझे मालूम हुआ, मैंने कलेक्टर को, कमिश्नर को कहा कि बिल्डिंग कैसे एलाट हो रही है। वे कमिश्नर थोड़े दिन के बाद बेचारे रहे नहीं, उनको हार्ट अटैक हो गया और मर गये। पर इसके बाद उस डिप्टी कमिश्नर लेबर ने स्वयं बिल्डिंग को अपने नाम अलाट करा लिया। मैं आप से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब केवल उसी परपज के लिए सैन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के लिए वह बिल्डिंग और वह जमीन सन् 1942 से आज तक आपके कब्जे में है, तो आपका जो डिप्टी डाइरेक्टर, लेबर है या जो आपका रेलवेज से एकाउंट्स आफिसर आन डेपूटेशन बना दिया गया है, उसका क्या अधिकार था उस बिल्डिंग को अलाट करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो अलाटमेंट के रूल्स बने हुए हैं, उसका फार्म होता है। उसने जान कर कि कोई न जाने, उसने स्वयं एक कागज पर लिख कर अलाटमेंट आर्डर की दरख्वास्त दी।

श्रीमन्, इस तरह से यहां पर जो खबरें भेजी गईं कि मजदूर कोई काम के लिए नहीं आता है, हमारे यहां .69 फी एकड़ बसे जो आदमी के ऊपर जमीन पड़ती है और बोझ इतना ज्यादा है कि 1,200 से लेकर, 1,300 फी वर्ग मील में लोग बसते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज धर्ती के ऊपर उनकी गुजर नहीं है और आज वे बच्चों को लेकर बाहर रोटी की तलाश में जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से तीन-चार सवाल करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इनके अफसरान जान भी गये होंगे। इन्होंने बड़ी कृपा की है कि जो उन्होंने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की स्कीम को एक्सैप्ट किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं। लेकिन तीन चार सवाल इनके सामने रखना चाहता हूं।

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय

पहला सवाल तो यह है कि क्या उस कलेक्टर के खिलाफ, श्री बलवंत सिंह के खिलाफ होम मिनिस्ट्री को लिख कर के उसका सस्पेंशन और उसका डिसमिसल, नौकरी से निकालने के लिए जिसने गवर्नमेंट बिल्डिंग को एक प्राइवेट आदमी के नाम से और एक आफिशल जिसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया, उसके नाम से जिसने एलाट किया, या दूसरा आफिशल जो डेपूटेशन पर है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही लेने के लिए होम मिनिस्ट्री को लिखेंगे ।

दूसरे सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की स्कीम को कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए मेरा निवेदन है कि क्लास फोर के एम्पलाई तो रखे ही जाएं पब्लिक सैक्टर में या और मजदूर रखे जाएं। लेकिन जो कोल-माइनर्स के बच्चे पढ़ कर के कोई हाई स्कूल हो गया है और कोई बी० ए० हो गया है, तो क्या उनको क्लास थ्री की सर्विसेज के लिए प्राविंशल या सेंट्रल सर्विस कमीशन्स से बातचीत करके इसी एम्पलायमेंट एक्सचेंज में एनरोल कर सकें उनके बच्चों को सर्विस देने के बारे में, क्या एक ऐसा एम्पलायमेंट एक्सचेंज इसी इन्स-टीट्यूशन को बनायेंगे ?

तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने उस करीब 11 एकड़ की जमीन को जो 11 एकड़ के करीब जमीन बिछिया में पड़ी हुई है क्या आपकी लेबर मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग के लिए जैसे सारे देश में सैंटर्स कई जगह खोले हुए हैं, जहां पर विधवाओं, महिलाओं, यतीम बच्चों और जहां पर ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं तथा बैगर्स पकड़े जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर कोई सैल्फ जेनरेटिंग इकनामी करने के लिए कोई स्कीम लागू करेंगे, जिससे कि हम उस जमीन का इस्तेमाल कर सकें।

आखिरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वहां के मजदूर जिन्होंने हजारों फीट जमीन के अंदर जाकर काम किया है, उनका बीस लाख रुपया स्टेट बैंक में अनक्लेम्ड एकाउंट में है और मैं आपको क्या बताऊं कि उस बीस लाख पर जो भी दो या ढाई लाख रुपया इंट्रेस्ट आता है, उस इंट्रेस्ट को बिना किसी गवर्नमेंट की सक्शन के उस डिप्टी डाइरेक्टर पी० सी० जोशी और एस० पी० सिंह ने एडवाइजरी कमेटी बना लिया और उसको आज दवा के नाम पर, डाक्टरों की एपाइंटमेंट के नाम पर खर्च किया जा रहा है। जब आप जानते हैं कि हर ब्लाक में आज प्राइमरी हैल्थ यूनिट हैं और हर जगह बड़े-बड़े अस्पताल हैं और गोरखपुर में मेडिकल कालेज तथा अस्पताल हैं तथा कमिश्नरी का बड़ा केन्द्र है, वहां पर क्या कमेटी को भंग कर उस रुपए के दुरुपयोग को रोकने के लिए कृपा करेंगे ?

आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि आप उस पैसे को उसी स्कीम में लगावें जो स्कीम आपके लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जिसकी आप रचना करना चाहते हैं, जिससे कि आप गरीबों को रोटी-रोजी दे सकते हैं जिससे कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो गरीब मजदूर हैं, वे आपको आशीर्वाद दे सकें, श्रीमती इन्दिरा गांधी को आशीर्वाद दे सकें और इस जनता पार्टी के जो 'प्राफेट आफ पीस' हैं, जो गरीब मजदूरों का नाम लेते नहीं थकते हैं, उनको दुत्कार सकें। इन्होंने आज ऐसी परिस्थिति कायम की है कि आज इतनी बड़ी सेन्ट्रल लेबर एम्पलायमेंट एक्सचेंज की स्कीम को तोड़ने की कोशिश की गई है, इसे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा स्वीकार नहीं करेगा।

श्री टी० अंजैया : उपसभाध्यक्ष जी, अभी पांडे जी ने कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया है। आप जानते हैं कि गोरखपुर के जो मजदूर हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं और अपनी स्टेट को छोड़ कर बहुत सी जगह दूसरे स्टेट्स में जाकर काम किया है। जैसा

मैंने कहा, वार के जमाने में उन लोगों ने एयरोड्रोम बनाने में, रोड्स बनाने में और माइन्स में काम करने में . . .

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (उत्तर प्रदेश) : मजबूर हैं, क्या करें?

श्री टी० अंजैया : . . . उन्होंने हर जगह जाकर काम किया है। जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं, अब परिस्थिति यह है कि 1970 में लगभग कोई 10,000 लोगों को मुलाजमत में जगह मिली हैं। 1971 में 9,000, 1972 में 9,000, 1973 में 2,000, 1974 में लगभग 2,000, 1976 में 1,400 तक ये फिगर्स हैं। दो एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज चल रहे हैं एक सेन्टर का और एक स्टेट का। तो दोनों एम्प्लायमेंट एक्सचेंज चलना मुश्किल हैं। या तो स्टेट गवर्नमेंट, यू० पी० गवर्नमेंट से कहें कि आप यहां का एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हटाइए, क्योंकि दो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज रहने का कोई मतलब नहीं। यह हो सकता है केवल कोल माइन्स के लिए रखा जाए। लेकिन इससे दूसरी स्टेट में भी यह बात आ सकती है कि हर जगह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कोल माइन्स के लिये अलग होने चाहिएं . . .

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : 27 मार्च का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में क्या करना है ? मंत्री जी के पास पड़ा है . . .

श्री टी० अंजैया : पाण्डेय जी जैसा कहेंगे उसको करने के लिए तैयार हूं। पीछे जाने का सवाल नहीं है। मैंने बताया, स्टेट में ट्रेनिंग सेन्टर हम खोल सकते हैं, 11 एकड़ की जगह हो। वीमेन ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल सकते हैं, हैंडिकैप्स के लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोल सकते हैं, जैसे आई०टी०आई० है, सी०टी०आई० है। उसके भी ट्रेनिंग सेन्टर खोल सकते हैं। बहरहाल 11 एकड़ में जो काम लेना चाहिए वह काम हम ले सकते हैं। अभी इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें दो आफिसर इन्वाल्व हैं। जहां तक हमको रिपोर्ट मिली है, एक आफिसर जो अभी रिटायर्ड है--जोशी जी का नाम बतला रहे हैं--वह बड़ी होशियारी से कलेक्टर से अपना नाम से अलाटमेन्ट कर लिए हैं और दूसरे आफिसर ने भी जो रेलवे से डेपुटेशन पर आया है, अपने नाम पर अलाटमेन्ट कर रखा है। यह किस तरह से गड़बड़ हुई है, यह बहुत बड़ा मिसयूज आफ पावर आफिशल्स ने जो किया है, इस पर मैंने डिपुटी डाइरेक्टर को, एडीशनल डाइरेक्टर को डिप्यूट किया है, वह रिपोर्ट कुछ रोज के अंदर आ जाएगी और उस रिपोर्ट के अंतर्गत जितना गवर्नमेंट ने ऐक्शन लेना है, वह काम करायेंगे। आगे जिस तरह की स्कीम हो सकती है, चाहे यू०पी० गवर्नमेंट से बातचीत करके। आप से बातचीत करके, वह करेंगे और इसलिए वाइन्ड अप करने का सवाल नहीं है। जब पाण्डेय जी ने यह बात बताई, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरह से मामला क्यों चला और क्यों इसके अंदर तमाम गड़बड़ नजर आती है। इस पर हम पूरे तरीके से विचार करेंगे। आप से बातचीत करके उस स्कीम को फिर से चालू करने में आपकी पूरे तरीके से सहायता करेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, लेबर डिपार्टमेन्ट हो या सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज महकमा हो, मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़े, एम्प्लायमेंट देश में बढ़े और क्योंकि बेकारी बढ़ती जा रही है, इसलिए हर माध्यम से हम लोगों को, बेकार लोगों को काम दें। यह मुख्य उद्देश्य है। लेकिन दुर्भाग्य से, बावजूद इसके कि सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज गोरखपुर में कहीं एक जगह हो, लेबर डिपार्टमेन्ट का हो, लेकिन इतनी योजनाओं के बाद हालत जो उभरी है वह यह है कि बेकारी बढ़ती ही गई। आपने कहा, स्टेट एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हैं, सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्चेन्ज भी

[श्री शिव चन्द्र झा]

हैं, दो इम्प्लायमेंट एक्सजेंज हैं। अब क्या जरूरत है? जिस उद्देश्य के लिए बना था अब उसकी जरूरत नहीं है। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द होल अफेयर। असली जो लोग हैं वे गड़बड़ कर रहे हैं। इस के अन्दर जाने की जरूरत है। यह कह देना काफी नहीं है कि हम पांडे जी की बात से सहमत हैं। आप ने पहले ही कबूल किया है अपने स्टेटमेंट में कि बहुत से अनस्किल्ड वर्कर्स हैं और माइन्स में भेजने की जरूरत नहीं है। कन्ट्रैक्ट लेबर खत्म हो गया है, स्टेट एक्सचेंज से काम चल जाता है, जो वहां है वह सरप्लस है और उस को जनरल यूज के लिए बदलने की बात है। लेकिन जो यूनिट बना हुआ था उस का दूसरे रूप में कहां तक ठीक से इस्तेमाल होता है, इस को भी देखने की बात है। जहां तक मुझे पता है, अफसरों की धांधली है, जो उस सारी जमीन को, मकान को, फर्नीचर को हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इसकी एकदम संकेड जांच कराइए कि क्या बात है हकीकत में?

दूसरी बात आप के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज देश में कितनी जगह हैं और रजिस्टर्ड अनएम्प्लायड लोग कितने हैं चाहे इस यूनिट में हों, चाहे सारे देश में हों। जहां तक मुझे पता है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड अनएम्प्लायड हैं। हमारे देश में चार करोड़ फुली होल टाइम अनएम्प्लायड हैं। इसलिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज सेन्ट्रल हो, स्टेट का हो—जो महकमा आप का पहले आसाम में रोड बनाने के लिए या क्या था वह अलग है बात— एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का जो मकसद है वह मकसद पूरा नहीं होता। जो मकसद आपने दर्शाया है उस की पूर्ति के लिए मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक पर एक हजार लोग एम्प्लाय किए जायं, सड़क, मकान, रोड वगैरह बनाने के लिए। हर आदमी को ब्लाक में दो सौ रुपया महीना आप दें। यह एक क्रैश प्रोग्राम के रूप में करें। आप को शायद पता हो कि न्यू डील के जरिए रूजवेल्ट ने सी सी कैम्प्स खोले थे, जब अमरीका में बेरोजगारी बढ़ गयी थी और ग्रेट क्राइसिस के बाद नौजवान बेकार घूमते थे। रूजवेल्ट ने कहा कि वह राष्ट्र जिन्दा नहीं रह सकता, जिस का नौजवान सड़क पर घूमे। उन्होंने एम्प्लायमेंट खोल दिया—चाहे सड़क काटो, नहर काट, बंध बनाओ। हर ब्लाक पर एक हजार आदमी एम्प्लाय हों और एक आदमी को दो सौ रुपया दिया जाय—खाने का काट कर बाकी घर ले जायेगा। हमारे देश में पांच हजार से कुछ ज्यादा ब्लाक हैं। एक-एक हजार आदमी प्रति ब्लाक के हिसाब से बहाल किए जाएंगे तो तुरंत जो पचास लाख अनएम्प्लायड वर्कर हैं उन की बेकारी खत्म हो जायगी और खर्चा भी आप को ज्यादा नहीं पड़ेगा। मैं ने हिसाब लगाया है कि 12,00 करोड़ साल में होगा। इस से सारे देश में 50 लाख लोगों को परमानेंट एम्प्लायमेंट मिल जायगा। जो पढ़े लिखे हैं उन के एम्प्लायमेंट का दूसरा रास्ता है। इस से देहातों में जो अनएम्प्लायड वर्कर हैं उन का एम्प्लायमेंट हो जायगा। तो इस तरह की योजना आप चलाएं। सेंट्रल एक्सचेंज से एम्प्लायमेंट कुछ होता नहीं वह करप्शन का ही अड्डा हैं। जिस का नाम भेजना चाहिए वह नहीं भेजा जाता। धांधली वहां बहुत है। बाकी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन यह हालत है। मेरा सवाल यह है कि जो बात उठी हुई है वह यह है कि गोरखपुर लेबर डिपार्टमेंट जो अंग्रेजों के जमाने से है, वहां धांधली अफसरों ने की है, उस की जांच के लिए क्या आप कोई हाई लेवल की कमेटी बनाएंगे और जो अफसर दोषी पाए जाएंगे, जिन्होंने मकान, जमीन, फर्नीचर हड़प लिया है उनको तुरन्त से तुरन्त दंड देंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अभी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में कितने रजिस्टर्ड अनएम्प्लायड हैं? तीसरा सवाल, एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज से पिछले दो साल में कितना एम्प्लायमेंट दिया

गया ? चौथा और आखिरी सवाल चूंकि यह एम्प्लायमेंट की बात है, सारे देश में एम्प्लायमेंट का जो क्रेश प्रोग्राम चलाने का मैंने सुझाव दिया है; क्या उसे लागू करने के लिए आप प्लानिंग कमीशन के सामने अपने सुझाव भेजेंगे ? ये मेरे चार सवाल है।

1 P. M.

श्री टी० अंजैया : उपसभाध्यक्ष जी, झा जी ने जो बातें बतायी हैं उन में जो अनइंप्लायमेंट का सवाल है उस के लिये तो जनता पार्टी ने भी वायदा किया था कि दस साल में वे देश में बेरोजगारी को दूर कर देंगे, मगर उन के काल में जितना अनइंप्लायमेंट देश में हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था हिन्दुस्तान की तारीख में। इसलिये कि पहले जो माल यहां बनता था उस को हम इस्तेमाल करते थे और बाहर का माल आने से रोका जाता था। अब बहुत सा माल बाहर से आता है और उस की वजह से लोकल एम्प्लायमेंट का भी सवाल उठता है। *(Interruptions)* वैसे देश में जब जरूरत हो तो हम भी माल बाहर से मंगा सकते हैं, लेकिन लोगों को एक आदत डालनी चाहिए कि देश में ही जो सामान बनता है उस को हम इस्तेमाल करें। आज फारेन गुड्स मिलने की वजह से बहुत से लोगों को देश में एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है। रेडियो है और दूसरे बहुत से सामान हैं जो मिलते हैं और बहुत से लोग फारेन माल खरीदने की ही कोशिश करते हैं। बाहर से स्मगलिंग से कपड़ा आदि आता है। तो उस को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम देश के गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये और बेरोजगारों के लिये कुछ करना चाहते हैं तो पहली चीज है कि देश में जो गुड्स बनती हैं उन को ही हम इस्तेमाल करें। ऐसा होने से देश में रोजगार बढ़ सकता है और बेरोजगारी को हम कम कर सकते हैं। इस के अलावा देश में जो रिसोर्सेज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्लानिंग की गयी है उस को टैप कर के हम अपना काम शुरू करें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हमारे देश में बढ़ सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से से बहुत सी बातें हैं, हम लोगों ने भी इलेक्शन में वायदा किया था कि हम एक फैमली में कम से कम एक आदमी को जाब देंगे। उस के लिये कोशिश की जा रही है कि कम से कम फैमली के एक आदमी को नौकरी जरूर मिल जानी चाहिए और इस के लिये हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं और मुमकिन है कि जल्दी ही इस पर हम कोई फैसला कर के एक पालिसी मेटर के तौर पर हाउस के सामने रख सकें।

श्री शिव चन्द्र झा : कितने अनएम्प्लायड हैं इस के फीगर्स तो दीजिए।

श्री टी० अंजैया : गोरखपुर के जो अनएम्प्लायड हैं उन के फीगर्स तो मैं दे सकता हूं *(Interruptions)* और अगर दूसरे फीगर्स ही आप चाहते हैं तो कल ही मैं आप को सारे फीगर्स दे सकता हूं, लेकिन आप ने तो यह सवाल पूरे देश के बारे में पूछा नहीं था। गोरखपुर के बारे में यह सवाल है। इस हद तक मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर के लिये अगर आप सेपरेट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज रखना चाहते हैं तो स्टेट का एम्प्लायमेंट एक्सचेंज रखें। *(Interruptions)* अगर आप चाहते हैं कि अफसरों को तनख्वाह दे कर हम हर महीने दो तीन लाख रुपया खर्च करते रहें तो मैं तैयार हूं लेकिन दो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज वहां चल नहीं सकते। वहां एक ही एम्प्लायमेंट एक्सचेंज होगा। गोरखपुर में एक स्टेट की तरफ से था और एक सेंटर की तरफ से था लेकिन अब उस की जरूरत नहीं है। जो बात झा साहब ने उठायी है, अफसरों के बारे में रिपोर्ट आती है अगर उन के काम के बारे में तो सरकार उन के खिलाफ एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगी और वहां उन के फायदे के लिये जो एक्टिविटीज होनी चाहिए उन में सरकार हर तरह से मदद करेगी और सहायता करेगी और हो सकता है कि इस तरह से काम होने से

कहां एम्प्लायमेंट बढ़े । इस ... लिये हम कोशिश कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Mrs. Pratima Bose. Not here. Yes, Dr. Bhai Mahavir.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Sir ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order, please. You had y°Ur chance and now let others have their chance.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I had my chance. But the Minister also should speak on what is mentioned in the Calling-Attention Motion. It says "non-implementation of the decision taken by Government after nationalisation of coal mines, for converting the Gorakh-pur Central Labour Department into a Central Employment Exchange", that decision was taken Ky'the Government and it was by an order of the President. It has not been done so far. *(Interruptions)* The building is there. The question of the Central Employment Exchange is there and the body is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): I think the honourable Minister has replied.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: It should not be mixed up between Central Employment Exchange and ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); The hon. Minister said that he is prepared to do what you want.

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): He is also ordering an inquiry into it.

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से जो जानकारी सदन के सामने आई है उससे मैं समझता हूं पांडेय जी ने बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने एक घोटाले की तरफ सरकार का और इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि यह जो सज्जन हैं डिप्टी डायरेक्टर (लेबर) जिन्होंने उस सारी बिल्डिंग को अपने नाम अलाट करवा लेने का एक जाल रचा और करवा लिया उनके इस कांड की खबर सबसे पहले आपको किस समय मिली ? आज मिली या इससे पहले पांडेय जी ने जब सरकार को दी थी तब सरकार को पता लगा अथवा सरकार इस बारे में पहले कोई जानकारी प्राप्त कर चुकी थी ? अगर कर चुकी थी तो क्या तत्काल इसकी जांच का कोई आदेश दिया गया ? और अगर आदेश दिया गया तो कृपया मंत्री जी यह बता दें कि इस जांच का परिणाम कब तक आपके पास आएगा, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे और क्या आप इस विषय में सदन को भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय वह जो बिल्डिंग है उस पर किस का अधिकार है और उस बिल्डिंग का क्या उपयोग हो रहा है जिसको उन्होंने अपने नाम एलाट करवाया था, जहां बैरेके बनी हुई हैं जिन बैरेकों में आपने कहा था कि एक लेबर ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम किया जा सकता है ? मैंने तो वह स्थान देखा नहीं है लेकिन जो जानकारी अभी मिली उसी के आधार पर मैं जानना चाहूंगा कि इस समय वह किस के अधिकार में है और इस समय उस बिल्डिंग का क्या उपयोग हो रहा है ? क्या उसका उपयोग सही हो रहा है या आज भी गलत लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ?

तीसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि यह जो आपने एम्प्लायमेंट के कुछ आंकड़े दिये

1970 से लेकर 1976 तक के उनसे ऐसा लगता है कि वह कम होते-होते आज नाम मात्र की एम्प्लायमेंट वहां पर दी जा रही है, उस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा । आखिरी आंकड़ा जो मैंने सुना है और मेरे ध्यान में रहा है वह यह है कि शायद 1,300 लोगों को वहां पर रोजगार दिलाने का प्रबन्ध इस रोजगार दफतर से हुआ है तो क्या 1,300 लोगों को ही साल भर में रोजगार दिलाने के लिये वहां पर आपने स्टाफ रखा हुआ है ? वह स्टाफ कितना है और उस स्टाफ के मैन्टेनेंस पर जो खर्चा होता है तो क्या वह उतने से काम के लिये सही है या इसलिये कि वह पहले से चला आ रहा है और सरकार का पैसा है, किसी के निजी जेब में से जाता नहीं है, सब मौज में बैठे हुए हैं और अफसरशाही वहां चल रही है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में वास्तव में आज एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक व्यय हो रहा है, क्या वह सचमुच इतने से काम के लिये आवश्यक और उपयुक्त नजर आता है अथवा इस बारे में सरकार को विचार करना पड़ेगा ?

इस के बाद महोदय, एक और मुद्दे पर मैं जानकारी चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि कांट्रेक्ट लेबर के नाम पर जो खदानों में लेबर रखी जाती है इसके लिये एक गोलमाल इस तरह से होता है कि जितने नाम सूची में रखे जाते हैं वास्तव में उतने 'लेबरर' रहते नहीं हैं और उसकी जो तनख्वाह होती है उसको वे कांट्रेक्टर लोग अपनी जेब में डालते हैं ? अगर इस तरह की कोई जानकारी मंत्री महोदय की नजर में है तो क्या सरकार ऐसी किसी जांच में भी भरोसा रखती है या कोई जांच इस बारे में करवाई गई है ? क्या सरकार गोरखपुर इलाके के लोगों को रोजगार दफ्तर में लाकर उनको इधर-उधर भेजती रहे यही सरकार का रोजगार देने का एक नक्शा है ? अभी मंत्री महोदय ने वहीं किया जैसा कि सभी मंत्रियों और उधर के माननीय सदस्यों का रिवाज है कि आखिरी की बात में जनता पार्टी को जब तक गालियां नहीं दे देते तब तक उनकी कोई रकम पूरी नहीं होती, तो उन्होंने भी कहा कि जनता पार्टी ने जो गड़बड़ की है उससे दो साल में बेरोजगारी बढ़ी है तो क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि जब इस देश में योजनाएं बननी शुरू हुई, अपने देश में बेरोजगारों का आंकड़ा 12 लाख का था ? और 12 लाख से आपकी पार्टी और आपकी सरकार के रहते आज तीन करोड़ से अधिक बेरोजगार इस देश के अन्दर हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इसका श्रेय किस को है ? जनता पार्टी को या आपकी नीतियों को ? मैं समझता हूं कि आपकी नीतियों और आपकी गलत कल्पनाओं को ही इसका श्रेय है । महोदय, मैंने इस संबंध में कुछ पाइन्टेड सवाल किये हैं । जनता पार्टी की सरकार ने कुछ निश्चय किये थे कि किस प्रकार से इस देश से बेरोजगारी को दूर किया जाय । आप जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कुछ विषयों को, कुछ पदार्थों को, रिजर्व किया था और यह कहा था कि ये चीजें बड़े कारखानों में नहीं बनेंगी, जैसे दियासलाई है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Please put only questions.

डा० भाई महावीर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नीति पर टिकी हुई है या नहीं कि जो पदार्थ छोटे पैमाने पर बनाये जा सकते हैं उनको छोटे पैमाने पर ही बनाया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके ? क्या आप इस नीति पर टिके हुए हैं या इसको बदल देंगे ? महोदय, उपयुक्त टेक्नोलोजी की बात बहुत बार हुई है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): You have already exhausted your time. Please conclude.

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलाजी सैल है और उसके जो परिणाम निकले हैं, क्या उनसे सरकार को संतोष है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उस सैल से उपयुक्त टेक्नोलाजी इवोल्व करने में कोई सहायता मिली है ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें ? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक फैमिली में एक व्यक्ति को नौकरी देने की जो बात कही गई है, यह नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सचमुच में क्या आप समझते हैं कि बिना उपयुक्त कामों का सृजन किये गांवों-गांवों में, देहात-देहात में आप तीन-चार करोड़ लोगों को रोजगार दे सकेंगे ? पिछले तीस सालों की नीतियों का परिणाम तो आप बताते रहते हैं, लेकिन आप मेरे इन नुक्तों का जवाब देने की कृपा करें ।

श्री टी० अंजैया : डा० भाई महावीर ने जो बातें बताई हैं उसमें बहुत-सी बातें कही हैं । एक तो उन्होंने ट्रेनिंग का सवाल किया । आई० टी० आई० में ट्रेनिंग दी जाती है । ये ट्रेनिंग सेन्टर सभी स्टेट्स में हैं । इनमें टेक्नोलोजी और इलैक्ट्रानिक्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है । अगर आप इन संस्थाओं को विजिट करें और उनके बारे में कोई सजेशन देना चाहें तो इससे ज्यादा फायदा हो सकता है । इस बारे में हम मेम्बरों को एक कमेटी भी डाल रहे हैं ताकि पार्लियामेंट के मेम्बर उसके अन्दर रहें और वे यह देख सकें कि क्या ट्रेनिंग हो रही है । वे यह बता सकते हैं कि इसमें क्या तबदीली करनी चाहिए । जितने भी लोगों को टेक्नीकल ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कुछ लोग बाहर भी जाते हैं और बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से भी बाहर जाते हैं । स्टेट गवर्नमेंट्स और सेन्ट्रल गवर्नमेंट, सभी ट्रेनिंग दे रहे हैं । इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो आप सजेशन देंगे, उस पर हम सोचने के लिए तैयार हैं ।

जहां तक आपने गोरखपुर की बात बताई है, जैसा मैंने कहा है, एक आर्डर निकला है । पहले एक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज चलता था, इसलिए एक इम्प्लायमेंट एक्सचेंज रखना है; क्योंकि यह सन् 1942 से रहा है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : लेकिन यह समस्या तो अब पैदा हुई है ।

श्री टी० अंजैया : एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के लिए काम होना चाहिए तभी उसको चलाया जा सकता है । अभी तक फीगर यह बताती है कि एक हजार से कम लोगों को काम मिल सका है ।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, क्या मंत्री महोदय मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं । मेरा सवाल यह है कि यह जो स्केन्डल हुआ है, कब से उसकी आपको जानकारी है और क्या आपको इस बात की भी जानकारी है कि उन दफ्तरों पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री टी० अंजैया : यह जो भी इन्फारमेशन मिली है उसके मिलते ही हमने अपने एडीशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को डिपूट किया । उसकी रिपोर्ट आने वाली है । उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है । यह काम कई साल से चल रहा है । उसकी जांच करने के लिए हमने आफिसर्स को भेजा है । उसकी रिपोर्ट आने वाली है । वह रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे । जहां तक हो सके, आफिसर्स जो भी गिल्टी होंगे हम निकालने की कोशिश करेंगे । . . . *(Interruptions)* जब मैं कहूंगा कि आप लोगों ने इसका एक्सटेंशन किया तो आप नाराज हो जाएंगे ।

डा० भाई महावीर : आपने अब क्या किया है, यह बताइये ।

श्री टी० अंजैया : मैंने बताया है कि हमने इस बारे में काम किया है। वहां पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज चल रहे हैं। आफिसर ने अपने नाम पर बिल्डिंग को अलाट करवा लिया कलेक्टर के जरिये से क्योंकि वह रैकेट था। रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। मैं रिपोर्ट को आपके सामने रखूंगा। यह नहीं हो सकता है कि मिनिस्टर गली-गली जा कर पूछताछ करे। टेलीविजन मेरे पास नहीं है कि हर एक चीज को अपने आप देख सकूं। जो इन्फार्मेशन आई है, पांडे जी ने जो इन्फार्मेशन दी है उसके बाद कार्यवाही हुई। उसके पहले मेरे पास फाइल आई थी। मैंने कहा मैं इसको क्लोज करने के लिये तैयार नहीं हूं। क्लोज करने के लिये मैंने कहा डज नौट अराइज नो, इसका सवाल नहीं है। जो भी हो सकता है एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में, वह करना चाहिए। मैंने फाइल वापस कर दी। बाद में रिप्रेजन्टेशन आया था। जब वह फाइल आई थी उसके अन्दर अच्छा हुआ कोई दस्तखत नहीं किये। फिर भी, मैंने आर्डर दिया है और एडीशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर चले गये हैं। मैं चाहा रहा था कि अगस्त में आपके सवाल का बन्दोबस्त कर लिया जाय ताकि मैं जवाब दे सकूं। मगर यहां से हुक्म हुआ कि आज ही इस बात का जवाब देना चाहिए। मैंने यह जवाब दिया है और जब रिपोर्ट आयेगी तो वह मैं आपके सामने पेश करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मोरारका) : मि० नागेश्वर प्रसाद शाही।

डा० भाई महावीर : श्रीमान्, मैंने . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA : No, please. Whatever answer h.» could give, he has given.

DR. BHAI MAHAVIR: Mr. Vice-Chairman, Sir, will you not protect u_s in the matler? At least, we expect the Mini te_r to answer certain points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Whatever answer he could give, he has given. If you are not satisfied ...

DR. BHAI MAHAVIR: We expect a better answer. He has to be just reminded to say whether the Government intends to continue the policy of reserving certain products which can be produced in the small sector for the smalj sector.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); He has said that a report would be placed on the Table o'f the House as soon as h_e gets it.

DR. BHAI MAHAVIR: That report is only *on* that particular episode, and not on the question of reservation for small units.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Shri Shahi, please.

श्री टी० अंजैया : आपने सवाल पूछा गोरखपुर में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जो धंधा चला रहा है, उसके बारे में आपने पूछा। अब उस सब चीज को लेकर . . .

डा० भाई महावीर : आपने कहा कि जनता पार्टी ने बेरोजगारी पैदा की तो मैंने पूछा है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order please. *(Interruptions)* . Mr. Nageshwar Prasad Sahi.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तरप्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के कार्यालय ने दुर्भाग्य से मंत्री जी को सारे तथ्यों से अवगत नहीं कराया। इस लेबर रेक्रूटमेंट डिपो ने, हालांकि इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, लेकिन 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

किया और जिस समय यह महसूस किया गया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं और तब जो बार्डर रोड आर्गनाइजेशन खड़ा किया गया तो उस बार्डर रोड आर्गनाइजेशन के सारे मजदूर इसी गोरखपुर डिपो ने सप्लाई किए थे, लाखों की तादाद में। नेफा और लद्दाख की सीमा पर जितनी सड़कें बनी हैं वे गोरखपुर डिपो के मजदूरों ने बनाई हैं और जो भी बार्डर रोड आर्गनाइजेशन के पास मजदूर हैं, उनमें से अधिकांश इसी संस्था के भेजे हुए हैं। मंत्री महोदय, आपके क्षेत्र में, गोलकुंडा की खानों में काम करने वाले मजदूर इसी लेबर रेक्रूटिंग डिपो के भेजे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में, मैसूर में, नेफा में, लद्दाख में, बिहार और बंगाल की कोयले की खानों में हजारों नीचे काम करने वाले और हजारों पहाड़ों की चोटी पर काम करने वाले मजदूर इसी लेबर डिपो के भेजे हुए है। यह महत्वपूर्ण है कि इस लेबर डिपो ने, जिस समय देश में संकट आया और जब कभी मजदूरों की आवश्यकता हुई, लाखों की संख्या में मजदूर दिये। मंत्री महोदय, आपने स्वयं कहा है कि जब-जब बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश की खानों में मजदूरों की कमी हुई तो इसी डिपो ने मजदूर सप्लाई किये। आज से सात साल पहले पाण्डेय जी भी लोक सभा में थे। उस समय अधिकारियों ने कोशिश की थी। श्रीमन्, यह कुछ ऊंचे अधिकारियों की साजिश थी कि इस डिपो को बन्द कर दिया जाए। क्योंकि वे इंट्रेस्टेड थे जैसे कि आपने स्वीकार किया। डिप्टी लेबर कमिश्नर उस बिल्डिंग और जमीन को हड़पना चाहता था। बिल्डिंग को तो करीब-करीब हड़प लिया है। वह जमीन को भी हड़पना चाहते थे। यह बिल्डिग और जमीन गोरखपुर शहर के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है और इसकी कीमत तीन करोड़ रुपये से ऊपर है। इस 11 एकड़ की जमीन और उस बिल्डिग की कीमत तीन करोड़ रुपये से ऊपर है। इसी के साथ-साथ गोरखपुर के कमिश्नर ने भी ऐसी हरकत की थी कि उसके बंगले के आस-पास 26 एकड़ सरकारी जमीन थी उसको जिस समय वे कमिश्नर थे उसी बिल्डिग में थे तो बंगले के पास 26 एकड़ जमीन को अपनी पत्नी के नाम से उसने काश्तकारी लिखवा ली। उस समय वहां के कमिश्नर मिस्टर निगम थे, उन्होंने तहसीलदार को बुलवा कर इशारा किया कि इस सारी जमीन को मेरी पत्नी के नाम से लिख दो। सरकारी खतौनी में, रेवेन्यू रिकार्ड में उनकी बीवी के नाम से सारी जमीन गुंदरी लिख दी गई। किसी तरह से मामला लीक हुआ। असेम्बली में सवाल उठा तो कमिश्नर ने जवाब भिजवा दिया कि नहीं यह गलत है। मामला छिपा दिया गया। फिर असेम्बली ने रिकार्ड को तलब किया तब कमिश्नर ने देखा कि अब तो पकड़े जाएंगे। रिकार्ड तलब हुआ। असेम्बली ने सारे रिकार्ड की जांच किया। लेकिन उसमें सारे पेजेज बदल दिए गए जिसमें कमिश्नर की पत्नी के नाम से सब इंदराज थे। उसी तरह से यह सवाल है। यह एक साजिश है और आपके अफसर कर रहे हैं। वे आपको यह कह रहे हैं कि यहां मजदूर आते नहीं हैं, संख्या घटती जा रही है। मेरा कहना यह है कि संख्या घटती नहीं जा रही है बल्कि घटाई जा रही है। क्योंकि वहां दो बिल्डिंग्स बंगला टाइप हैं। उनको दो अधिकारियों ने कब्जा कर लिया। एक है रिटायर्ड अफसर मिस्टर जोशी जो डिप्टी कमिश्नर थे और दूसरे हैं मिस्टर सिंह जो इस समय आए हैं। अब केवल बैरक्स रह गए हैं;

उस बैरक और जमीन को भी अपने नाम करने की साजिश है । इसलिए पिछले सात साल से यह कोशिश चल रही है कि इस डिपो को बन्द कर दिया जाए। जब हम लोगों को मालूम हुआ, तो स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम साहब उस समय मिनिस्टर थे । उनके पास हम लोग डेपुटेशन ले कर गए और उनसे रिक्वेस्ट किया । तब उन्होंने उस एरिया के एम०पीज और अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई । उस मीटिंग में यह हुआ कि डिपो को चेंज कर के एम्पलायमेंट एक्सचेंज बना दिया जाएगा और उन्होंने यह भी एनाउंस किया कि एम० पीज की मीटिंग में यह भी तय किया गया कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजज का काम इतना ही नहीं होगा कि मजदूरों की भर्ती करेगा बल्कि यह भी होगा, चूंकि वह बैकवर्ड एरिया था और कोई काम नहीं है। लाखों मजदूर वहां पर हैं जो पंजाब, हरियाणा और दूसरी सब जगहों पर जाते हैं, उन्होंने वायदा किया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह सेंटर सर्वे और रिसर्च भी करेगा टू जेनरेट एम्प्लायमेंट इन दैट एरिया। मंत्री जी, आप इसको नोट कीजिए । स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम साहब ने यह वायदा किया था । (*Interruptions*) आप ठीक कह रहे हैं कि वहां स्टेट गवर्नमेंट का भी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज है, दोनों कैसे चलेंगे । लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कहा था कि इसका परपज वाइडर होगा । उस बैकवर्ड एरिया में एम्प्लायमेंट कैसे जेनरेट किया जाए, इसमें रिसर्च होगा और सर्वे होगा । मैं आपसे निवेदन करता हूं। (*Time bell rings*) मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आप इस पर विचार करेंगे कि जैसे माननीय स्वर्गीय कुमारमंगलम साहब ने वायदा किया था कि इस सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा This centre will be used for survey and research for generating employment in that area. आप क्या इसको इसलिए इस्तेमाल करेंगे, इतनी बड़ी जमीन है, बिल्डिंग है, आसानी से काम हो सकता है । एक और बात है श्रीमन्, इतने दिनों से मजदूर जो वहां कमा रहे हैं, उन मजदूरों की मजदूरी में से काट कर करोड़ों रुपया वहां इकट्ठा है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : 20 लाख रुपया ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हां, और यह एमाउंट अनक्लेम्ड है । उसको ये अधिकारी हड़प जाना चाहते हैं । उसका परपज यह था कि वहां पर जो वर्कर्स रिक्रूट हुए हैं उनकी हैल्थ के लिए, उनके परिवारों की इम्दाद के लिए और सब वैलफेयर स्कीम्स के ऊपर इसको खर्च किया जाय । वह सारा पैसा पड़ा हुआ है और उसको अधिकारी हड़पना चाहते हैं । क्या आप आश्वासन देंगे कि इस क्षेत्र के संसद् सदस्यों की एक कमेटी बनायी जायगी जो उस धन के उपयोग के बारे में सुझाव दे सकें ताकि उस क्षेत्र के गरीबों का, मजदूरों का कल्याण हो सके । क्या ऐसी कमेटी बनाने का सुझाव देंगे और जैसा मैंने कहा कि वादा किया था तो उसके बारे में आश्वासन देंगे ?

श्री टी० अंजैया : शाही जी ने बहुत सी बातें बतायी हैं । उनकी बातों से मुझे कोई मतभेद नहीं है ; क्योंकि उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट, लोगों के डेवलपमेंट करने और रोजगार के बारे में कहा है । जहां तक मिसयूज का

[श्री टी० अंजैया]

सवाल है मैंने पहले भी कहा कि उनके ऊपर एक्शन लिया जायगा । जो पैसा जमा हुआ है जैसा वे बता रहे हैं 10 लाख और उनका यह कहना है कि उसमें अब तक कितना जमा हुआ था, कितना खर्च किया गया, किस-किस पर खर्च किया गया, डिस्पेंसरी पर कितना खर्च हुआ, ओल्ड ऐज पेंशन पर कितना खर्च किया गया तो इन सब चीजों की जांच पड़ताल के लिए मैंने कहा है कि इन सबकी जांच पड़ताल हो । अब जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का सवाल है । जैसे कि हमने आंध्र प्रदेश में शुरू किया था कि एम एल एज और एम पीज को उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट वाइज डालते थे, उसी तरीके से अब मैं बहुत जल्दी फैसला करने वाला हूं कि सेन्ट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में भी एडवाइजरी कमेटी बने, स्टेट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज एडवाइजरी कमेटी बने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हम एम एल एज और एम पीज को इन्वाल्व करने की सोच रहे हैं । अतः जो एम्प्लायमेंट की पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में है वह एम० पी० को मालूम होनी चाहिए कि कितना अनएम्प्लायमेंट है, क्या पोजीशन है । एम्प्लायमेंट में कैसे मिस यूज हो रहा है, सीनियारिटी या इसकी उसकी जो धांधलियां चल रही हैं, इन तमाम चीजों को देखने के लिए विजिलेंस कमेटी एम एल एज, लोकल ट्रेड यूनियन लीडर्स, सोशलिस्ट वर्कर्स और जर्नलिस्ट्स की बननी चाहिए जैसे कि हमने पहले बनायी थी । अब यह काम करने के लिए भी हम सोच रहे हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हो सकेगा गवर्नमेंट की तरफ से, हर तरीके से इस बात की कोशिश की जायेगी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : कुमारमंगलम ने जो वादा किया था ।

श्री टी० अंजैया : मैं पीछे नहीं जा रहा हूं शाही जी । अब आप सोच लीजिए कि जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं, वे पिलग्रिम्स तो हैं नहीं । पिलग्रिम्स बन जायेंगे तो कैसे होगा । दो एक्सचेंज चल रहे हैं, अब एक एक्सचेंज तो क्लोज करना पड़ेगा . . . *(Interruptions)* मैंने कहा कि उसमें आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा । आप लोगों की मीटिंग बुलायी जायगी । जितने स्पीकरों ने बातचीत की है उनकी मीटिंग बुलाएंगे । हम सब मिल कर जायेंगे । जो आप कहेंगे वह मैं करूंगा । इसके अंदर मुझे करना है तो लोगों के लिए करना है । उसके अंदर गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपकी एडवाईस लेकर जो अच्छा होगा उसको करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा ।

SHRI P. RAMAMURTI: The coalmines are situated in Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar, partly in Orissa and in Madhya Pradesh. As far as Bengal is concerned, the coalmine workers come mostly from Bihar and from Orissa as well as from Gorakhpur district. Therefore, in order to co-ordinate the activities of recruitment of these people and to see that there is not much overlapping or much weightage given to people from *on%* State, will the Central Government think of opening employment exchanges for coalmines separately in all these five States and also for having a co-ordinating organisation so that they are distributed properly among the coalmines in all these areas? This is the only question I want to ask.

श्री टी० अंजैया : जो सजेशन राममूर्ति जी ने किया है इसको हम सोच सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी कितनी है और उसके क्या प्रभाव वहां के रहने वालों पर पड़ते हैं। यह केवल गोरखपुर का प्रश्न नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि जोत बहुत छोटी है और जितने भी आस-पास के जिले हैं वे गोरखपुर में आते हैं। और यह गोरखपुर एक केन्द्र रहा है उस सारे क्षेत्र के बेरोजगारों के रोजगार मिलने का और यहां से कलकत्ता को, पूर्वोत्तर भारत में असम वगैरह हो या कोयले के खदानों में हो या दूसरे कारखानों में हो, लोग जाते रहे हैं। यह जो कोयले के खदानों में लोग जाते थे, उसमें शोषण भी वहां के गरीब का बहुत होता था। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो गया, उसके बाद उस संस्था की बुराइयों को खत्म भी किया और इस तरीके को भी खत्म किया कि जिससे वहां शोषण होता था। लेकिन मौलिक प्रश्न बना रहा कि रोजगार कैसे मिले और वहां की जमीन में अब और इससे अधिक भार सहन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए वहां के लोगों को रोजगार मिलना तो आवश्यक है ही। इस पृष्ठ भूमि में यह जो सारे सुझाव आपके सामने आए, कुमारमंगलम साहब के सामने आए, बाद में जब मैं एनर्जी मिनिस्ट्री में था, उस वक्त मेरे सामने भी आए। 1976 में नोटिफिकेशन भी हुआ।

अब यह दुःख की बात है कि जिस उद्देश्य से यह काम शुरू हुआ था उसकी पूर्ति की तरफ बढ़ने की बजाए हम उससे पीछे हटे, जिन उम्मीदों से इसको बनाया गया था उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए तो दूर रहा, उसके बाद साहस कम हो गया और जो जमीन इमारतें मिली थीं, जिस उद्देश्य से वह दी गई थीं, उस उद्देश्य की पूर्ति करने की बात तो दूर रही, आज प्रश्न यह उठ रहा है कि उनका क्या करें, किसको दें, कोई अफसर उसको ले ले, पैसे का क्या करें ?

तो मैं मंत्री जी से एक सुझाव यह देना चाहता हूं और एक सवाल भी करना चाहता हूं कि क्या वे इसके लिए तैयार हैं कि जहां जमीन भी हो, जहां इमारतें भी हों, जहां इतना बड़ा प्रश्न हो बेरोजगारी का, वे इन सब चीजों को सोच कर के एक ऐसी पायलट स्कीम की तरह से वहां खोलें जिससे उस जमीन का भी इस्तेमाल हो और उन इमारतों का भी इस्तेमाल हो, जिस उद्देश्य से सारी स्कीम शुरू हुई थी। उसकी भी पूर्ति हो और उस पायलट स्कीम में जो स्थानीय रोजगार के मौके हैं, उनका ध्यान करके और दूसरी जगह भी जो हैं, उनका भी ध्यान करके सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी के प्रश्न को हल करने की तरफ कुछ बढ़ सकें, इसके लिए पायलट स्कीम और पायलट स्टडी का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम एक समिति बनाने का फौरन आश्वासन दे दें जोकि इस उद्देश्य से सारी चीजों को ध्यान करके इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके योजना दे, इसको कार्यान्वित करे ताकि जिस उद्देश्य से इसको शुरू में बनाया गया था, उसकी पूर्ति हो सके।

श्री टी० अंजैया : पन्त जी ने जो बताया है उसके अन्दर दो बातें हैं। एक तो जिस मकसद से यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज गोरखपुर में खोला गया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको बिलकुल एक अलग ढंग से खत्म किया जा रहा है। यह तो मैं मानता हूं। इसको मैंने भी कहा कि इसके अन्दर मिसयज हुआ है, तमाम बहुत गड़बड़ था। इस गड़बड़

[श्री टी० अंजैया]

होने की वजह से जब फाइल मेरे पास आई तो उसमें मैंने सोचा कि इसके अन्दर गड़बड़ है, तो मैंने साइन ही नहीं किया मगर इसकी जांच-पड़ताल पूरी होगी। जो भी अफसर इसमें इन्वाल्व होंगे, उनके ऊपर एक्शन लिया जायगा । कुछ लोग तो रिटायर हो गये हैं । रिटायर होने के बाद उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, यह भी हम सोचेंगे । यह नहीं कि ऐसे आदमी जिन्होंने मनमानी किया है, इसके अन्दर कौन-कौन इन्वाल्व्ड हैं, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ वह भी मालूम करेंगे । जहां तक दूसरे प्रोपोजल हैं कि इसकी कुछ कमेटी एम्पलायमैंट एक्सचेंज पूरे उत्तर प्रदेश के लिये . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए।

श्री टी० अंजैया . पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, उस रीजन के लिए जो बनाने के लिए उन्होंने कहा है, हम हर प्रोपजल को जो अच्छा हो सकता है उस रीजन के लिए, वह सोच सकते हैं । उसकी रिपोर्ट आते ही मैं आप लोगों से फिर डिसकस करूंगा । जैसा आप कहेंगे, मैंने पहले ही कहा कि पायलट स्कीम के लिए जो स्कीम बन सकता है उस प्रान्त के लिए, वह हम करने के लिए तैयार हैं ।

REFERENCE TO THE REPORTED LATHI CHARGE BY POLICE ON LOK DAL WORKERS IN MEERUT ON THE 28TH JULY, 1980

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, ऐसा लगता है कि जब से माननीय जैल सिंह गृह मंत्री बन कर आए कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन जनता के ऊपर लाठी चार्ज और गोली चार्ज नहीं होगा क्योंकि माननीय जैल सिंह जी को तो जुडिशल इंडिक्टमेंट हो चुका है, उन के ऊपर साबित हो चुका है कि वे अपने शासन काल में पार्शलिटी बरते हैं, निपोटिज्म किए हैं फेवरिटिज्म किए हैं । ऐसे व्यक्ति से हम आशा ही और नहीं कर सकते हैं । एक अच्छे सेन आदमी को उन्होंने पागल बना कर जेल में बंद कर दिया । ऐसे व्यक्ति से हम क्या आशा कर सकते हैं जो देश का गृह मंत्री है ? स्वाभाविक है कि देश के कोने-कोने में रोजाना गोली चले और लाठी-चार्ज हो । इस समय आप देख रहे हैं कर्णाटक में क्या हो रहा है ? रोजाना गोली चलायी जा रही है । गोली से कम कोई बात नहीं हो रही है । किसान, मजदूर, विद्यार्थी सब पर गोली चल रही है ।

श्रीमन्, यह विशेष घटना है मेरठ की । मेरठ में लोक दल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने इतनी बर्बरता के साथ ।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : कोई मंत्री यहां नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: पुलिस ने इतनी बर्बरता के साथ उन पर लाठी चार्ज किया कि सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए । श्रीमन्, आप इसको इस कांटेक्स्ट में देखें कि आखिर हो क्या रहा है ? जहां कोइ नाम लेता है बागपत कांड का, जहां कोई नाम लेता है माया त्यागी का, उसके ऊपर पुलिस का डंडा, पुलिस की गोली शुरु हो जाती हैं । श्रीमन्, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, उसी बागपत के पास द्रोपदी का चीर-हरण हुआ था, उसी बागपत के पास भगवान श्री कृष्ण ने उस महिला की लज्जा बचा ली थी । तब भी केवल प्रयास हुआ था चीर हरण का, कौरवों का राज्य चला गया और उसी स्थान पर, बागपत में, इस महिला का चीर-हरण हुआ है । . . .

(Interruptions)